MR. CHAIRMAN: No reference against a State or the Administration will be allowed to go on record. On other things, yes.

The Punjab and Maharashtra Co-operative (PMC) Bank crisis

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

महोदय, मैं यहाँ पर पीएमसी का मामला उठाना चाहता हूं। आरबीआई को इस मामले में जिस तरह से intervene करना चाहिए था, उसने वैसे नहीं किया, आरबीआई इस मामले में फेल हो गई। HDIL को 2,500 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन उस रकम को ठीक ढंग से regularize नहीं किया गया। 100 करोड़ रुपये का लोन डिटेक्ट करने में 55 महीने, यानी साढ़े चार साल लग गए। वहाँ जिनके accounts थे, वे बेचारे लोग यहाँ-वहाँ, हर जगह घूम रहे हैं, कई लोग तो shock से मर भी गए हैं।

महोदय, नाबार्ड की एक "इंद्रधनुष स्कीम" थी, जिसमें 2 लाख, 11 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन उस रकम का क्या हुआ, यह किसी को मालूम नहीं है।

महोदय, समय का अभाव है, इसलिए मैं इस matter को जल्दी में बोल रहा हूं कि CKP Cooperative Bank का मामला 2014 में हुआ था, उसके लिए फंड फिर से दिए गए थे, लेकिन उस मामले का क्या हुआ, वह भी हमें अभी तक मालूम नहीं है। Insurance amount के लिए बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स की जो countries हैं, वहाँ भी 12 लाख रुपये का amount रखा गया है, जबकि यहाँ पर 1 लाख रुपये का amount ही दिया जाता है। मेरा ऐसा कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जहाँ 100 करोड़ रुपये का लोन दिया जाता है, वहाँ उसकी मालूमात करने में इतने दिन लग जाते हैं, साढ़े चार साल तक लग जाते हैं, इसलिए इसकी कोशिश करनी भी बहुत जरूरी है वह रकम जल्दी से जल्दी मिले।

महोदय, मेरी आपसे ऐसी दरख्वास्त है कि पीएमसी के जो account holders हैं, उन्हें उनके पैसे वापस मिलें, इसके लिए सरकार का इस मामले में कहीं न कहीं intervene करना जरूरी है। सर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। मैं zero hour submission थोड़ा liberally allow कर रहा हूं, लेकिन यह भी देख रहा हूं कि कभी-कभी एक ही पार्टी के चार-पाँच submissions भी आ रहे हैं।

विषय के महत्व को ध्यान में रख कर और जिन्होंने पहले नोटिस दिया है, उनकी

12.00 NOON

priority को ध्यान में रख कर मैं उन्हें allow कर रहा हूँ, मगर माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध यह है कि कृपया विषय के ऊपर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करिए। अगर इसमें आरोप वगैरह करने की प्रवृत्ति बन गई, तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो इसको रोकना या पहले से ऐसा कौन-कौन लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान में रख कर ऐसे महानुभावों को कम अवसर देना, आगे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसलिए कृपया सब लोग इसको ध्यान में लीजिए।

Now, we will move on to Question Hour.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Conflict over the practice of 'intergative medicine'

*151. DR. SANTANU SEN: Will the Minister of AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) pleased to state:

(a) whether the Minister is aware of the growing differences between Ministry of AYUSH and Ministry of Health and Family Welfare's National Health Authority (NHA) over the practice of integrative medicine'; and

(b) if so, the details of alternative treatments that the AYUSH Ministry has talked about?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) There are no differences between Ministry of AYUSH and Ministry of Health and Family Welfare's National Health Authority (NHA) over the practice of 'integrative medicine'.

(b) In view of (a), the question does not arise.

DR. SANTANU SEN: Sir, my first supplementary is this. As you all know, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy are age old systems of medicine of